**आल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन**

**एलआईसी बिल्डिंग, सेक्रेटरी रोड हैदराबाद – 500 063**

**(ई-मेल:****aiieahyd@gmail.com****)**

सर्कुलर नंबर: 29/2020 दिनांक – 03/08/2020

प्रति,

सभी जोनल / मंडल / राज्य / आंचलिक इकाइयाँ

प्रिय कामरेड्स,

**एआईआईइए सचिव मण्डल ने दिनांक 02/08/2020 की बैठक में निम्न निर्णय लिया –**

**एलआईसी की लिस्टिंग और आईपीओ के खिलाफ अभियान और आंदोलन को तेज किया जाय**

**सार्वजनिक क्षेत्र की आम बीमा कंपनियो के एकीकरण की मांग के लिए व्यापक जनमत जुटाया जाय**

**सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की नीति के खिलाफ संघर्ष को गहरा और व्यापक किया जाय**

**सभी स्तरों पर संगठन को मजबूत किया जाय**

AIIEA सचिव मण्डल की एक बैठक 02 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। इस ऑनलाइन बैठक को उद्योग के भीतर और बाहर के घटनाक्रमों की समीक्षा हेतु बुलाया गया था, ताकि आगामी डीनो में वेतन पुनर्निर्धारण के मुद्दे पर कार्रवाई हेतु उस अनुरूप सभी स्तरों

पर संगठन को विकसित व संगठित किया जा सके। इस बैठक में कॉम सुरजीत दास, महासचिव, EZGIEA, जो स्वास्थ्य के कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, को छोड़कर सचिवा मण्डल के सभी सदस्यों ने भाग लिया। । **सचिव मण्डल की बैठक को कॉम. अमानुल्ला खान और कॉम. के. वेणु गोपाल की उपस्थिति और मार्गदर्शन का लाभ भी मिला।**

सचिव मण्डल का स्पस्त मत था कि COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक गतिविधियां ध्वस्त हो गई है। यह वास्तव में किसी भी संदेह से परे, उजागर हो गया है कि मुक्त बाजार पर अपनी विशेष निर्भरता के साथ पूंजीवाद लोगों की वास्तविक चिंताओं को दूर करने में पूरी तरह विफल रहा है। सचिव मण्डल ने नोट किया कि विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 80 वर्षों में सबसे गहरी मंदी का सामना कर रही है। बैंक ने 2020 में वैश्विक जीडीपी में 5.2 प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है। सचिव मण्डल ने यह बी नोट किया कि आईएमएफ ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकुचन के बारे में इसी तरह के अनुमान लगाए है । भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही स्व अधिरोपित विमुद्रीकरण और गैर नियोजित जीएसटी के कारण गहरी मुसीबत में थी। COVID-19 महामारी और अचानक कि गई तलबन्दी की घोषणा ने समस्याओं को और भी गहरा कर दिया है। भारत की आर्थिक वृद्धि 2019-20 में अनुमानित 4.2 प्रतिशत रही, जो पिछले ग्यारह वर्षों में सबसे कम थी। हालांकि, विभिन्न वैश्विक और घरेलू एजेंसियों द्वारा चालू वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि के बारे मे तेज संकुचन -3.2% से -9.5% तक होने का अनुमान लगा रहे हैं। इस संकट का सबसे बुरा प्रभाव समाज के श्रमिकों और हाशिये पर पड़े वर्गों पर पड़ा है। सचिव मण्डल ने ध्यान पूर्वक यह भी नोट किया कि इस समय गरीबों और जरूरतमंदों के पक्ष में खड़े होने के बजाय सरकार इस संकट का उपयोग अपने नवउदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। श्रमिकों के अधिकारों पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और श्रमिक वर्ग को पूंजीपति की गुलामी के लिए मजबूर कर दिया जाय फिर भी वे उसकी निंदा भी न कर सकें इसलिए श्रम कानून भी बदल दिए जाते हैं। भारत के प्रधान मंत्री स्वयं कहते हैं कि “वह खुद इस संकट में एक अवसर देख रहे हैं”। संकट के इस मौके को भी सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण हेतु इस्तेमाल करने के लिए लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे वित्तीय क्षेत्र, बंदरगाहों, खानों, अंतरिक्ष, रक्षा, रेलवे आदि को पूरी तरह से निजी पूंजी के लूट के लिए खोला जा रहा है। सरकार जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है वह गंभीर रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर हो गई है।

सचिव मण्डल ने महसूस किया कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी एलआईसी शानदार प्रदर्शन कर रही थी । वित्त वर्ष 2019-20 में LIC ने अपने प्रथम प्रीमियम आय में 25.17% की वृद्धि दर्ज कर ₹1,77,977.07 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है जो अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। एलआईसी के पेंशन और स्मूह बीमा व्यवसाय ने एक लाख करोड़ के जादुई आंकड़े को पार करके ₹1,26,696.21 करोड़ रुपये जुटाए और 39.46% की वृद्धि दर्ज कर एक इतिहास रचा। निगम ने वित्त वर्ष में ₹3,79,062.56 करोड़ रुपये की कुल प्रीमियम आय एकत्र कर 12.42% के वृद्धि दर्ज की। LIC की सकल कुल आय 9.83% वृद्धि के साथ बढ़कर ₹6,15,882.94 करोड़ रुपये और 31.03.2020 तक कुल सम्पत्ति ₹31,96,214.81 करोड़ रुपये थी। सचिव मण्डल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इस संकटपूर्ण परिस्थिति मे भी एलआईसी द्वारा इस तरह के शानदार प्रदर्शन के बावजूद, भारत सरकार प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में एलआईसी को सूचीबद्ध करने के निर्णय के साथ आगे बढ़ रही है।

अब सरकार ने इस महामारी को भी एक अवसर के रूप में भुनाने की नीयत से इस संकट का दुरुपयोग करते हुए, सरकार को सलाह देने के लिए लेनदेन सलाहकारों को आमंत्रित करने और चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने डेलॉइट टच तोहमित्सु और एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज को सलाहकार के रूप में चुना है। AIIEA ने इसे निजीकरण की दिशा में पहला कदम माना और संयुक्त मोर्चा के अन्य दो सदस्यों के साथ वित्त मंत्री को एलआईसी की विनिवेश प्रक्रिया की दिशा मे आगे नहीं बढ़ने के लिए एक पत्र भी लिखा है। संयुक्त मोर्चा ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुखों को भी पत्र लिखकर हमारे संघर्ष के लिए समर्थन मांगा है। सरकार हालांकि LIC में अपनी 5 से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का इरादा रखती है। मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आईपीओ के साथ बाजार में आने की उम्मीद है। सचिव मण्डल ने महसूस किया कि एलआईसी की लिस्टिंग और विनिवेश के खिलाफ हमारे अभियान और संघर्ष को तेज करने की आवश्यकता है।

सचिव मण्डल ने सार्वजनिक क्षेत्र की आम बीमा कंपनियों (PSGI) के प्रदर्शन की सराहना की। भारत में सक्रिय पच्चीस जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (सात स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों और दो विशेष बीमा कंपनियों को छोड़कर) जून 2020 तक 6% की नकारात्मक वृद्धि के साथ समाप्त हुई हैं। चारों पीएसजीआई कंपनियां हालांकि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी नकारात्मक वृद्धि को 1.41% तक कम कर सकती थीं। इन चारों पीएसजीआई कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 47.93% है। सचिव मण्डल ने नोट किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विलय को रोकने के फैसले को मंजूरी नहीं दी। सचिव मण्डल का मानना है कि, यदि सरकार महामारी के दौरान भी बैंकिंग क्षेत्र के एकीकरण के साथ आगे बढ़ सकती है, तो सरकार के पास इस बात का कोई कारण नहीं है कि पीएसजीआई कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को बंद वह कर दे। बैठक कि यह राय थी कि , सरकार के इस फैसले के पीछे कि मंशा संदिग्ध और गुप्त है और विलय को रोकने का असली इरादा इन तीन कंपनियों में विनिवेश करना है। सचिव मण्डल ने सभी चार कंपनियों (न्यू इंडिया सहित) के विलय की मांग करते हुए हमारे संघर्ष को जारी रखने का फैसला किया और इस मुद्दे पर सामान्य बीमा में एकता का विस्तार करने की कोशिश करने और पीएसजीआई कंपनियों के विनिवेश के खिलाफ एक गंभीर लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

सचिव मण्डल ने एलआईसी और पीएसजीएस कंपनियों में वेतन पुनर्निर्धारण के मुद्दे के निपटारे में होने वाली भारी देरी पर असंतोष व्यक्त किया। सचिव मण्डल इस बात से विशेष रूप से असंतुष्ट था कि आज तक GIPSA प्रबंधन PSGI कंपनियों में कोई ठोस प्रस्ताव लेकर नहीं आया । बैठक ने फैसला किया कि एलआईसी और जिप्सा प्रबंधन दोनों को बिना किसी अनिश्चितता के हमे स्पस्ट रुप में बताना होगा कि इस मुद्दे पर कोई और देरी स्वीकार नहीं हो सकती है और प्रबंधन को ठोस प्रस्तावों के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए ।

सचिव मण्डल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आज हर क्षेत्र में संघर्ष विकसित हो रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध और लॉकडाउन की स्थिति मे श्रमिकों को नवीन तरीकों के माध्यम से संघर्ष शुरू करने से कोंई बाधा नहीं रोक पायी है। कोयला मजदूर जुलाई में तीन दिवसीय ऐतिहासिक हड़ताल पर चले गए और वे इस महीने की 18 तारीख को एक और हड़ताल कि योजना बना रहे हैं।

बिजली कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, वकील, डॉक्टर संघर्ष की राह पर हैं। सचिव मण्डल को यह जानकर खुशी हुई कि केंद्रीय शरमीक संघों के राष्ट्रीय मंच ने क्षेत्र आधारित संगठनों और विभिन्न सेक्टर के संगठनों के साथ, 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बैठक ने सभी संगठनों की इसलिए भी सराहना की, कि राष्ट्रीय मंच ने 18 अगस्त को सभी कार्यस्थलों पर देशव्यापी एकजुटता दिखाने और विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई करने का फैसला किया है, क्योंकि इस दिन कोयला श्रमिकों ने निजी वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक के आवंटन के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। सचिव मण्डल का यह दृढ़ मत था कि इससे सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन बनाने की एक प्रबल संभावना उपलब्ध है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, सचिव मण्डल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए –

* स्टॉक एक्सचेंज में एलआईसी को सूचीबद्ध करने के सरकार के विनाशकारी प्रस्ताव के खिलाफ कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच व्यापक अभियान चलाया जाय । इस अभियान मे यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पालिसी धारकों को साथ ही यह आवश्यक विश्वास भी दिलाया जाय कि एलआईसी में जागरूक ट्रेड यूनियन आंदोलन उनके हितों की रक्षा करने संघर्षत और प्रतिबद्ध है । हमारे अभियान व हमारे संघर्ष में पालिसी धारकों का समर्थन जुटाना होगा।
* समाज के शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और नीति निर्माताओं के बीच व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए और उन्हें सही मायनों में हमारा पक्ष लेने के लिए अनुरोध करना होगा।
* सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों / प्रमुखों को पत्र लिखकर उनसे एलआईसी को शेयर बाजार मे सूचीबद्ध किए जाने और विनिवेश का प्रस्ताव संसद मे जब भी लाया जाएगा उनसे इसका विरोध करने का अनुरोध किया गया है ।
* **9 अगस्त 2020** का दिन सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए, **भारत छोड़ो दिवस- एलआईसी / पीएसजीआई और सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ दिवस** के रूप में मनाया जाए
* **18 अगस्त 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ दिवस** के रूप में मनाया जाय और **हड़ताली कोयला श्रमिकों** के साथ एकजुटता व्यक्त करें।
* **यदि सरकार एलआईसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए किसी विधेयक को लाती है या एलआईसी में अपनी अंशधारिता को कम करने के लिए कोई अध्यादेश लाती है, तो तुरंत एक दिन की हड़ताल पर जाने के लिए तैयार रहें।**
* विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को गहरा और व्यापक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ें।
* एलआईसी मे आईपीओ के खिलाफ और वेतन पुनर्निर्धारण के संघर्ष पर एक आम समझ कायम करने के लिए एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस में अन्य यूनियनों से संपर्क एक आपसी समन्वय विकसित किया जाय ।
* **न्यू इंडिया सहित सभी चार आम बीमा कंपनियों के विलय की मांग पर अपने अभियान को जारी रखने के लिए और आम बीमा कंपनियों के विनिवेश के खिलाफ गंभीर लड़ाई के लिए तैयार रहें।**
* LIC में वेतन वार्ता को फिर से बहाल करने के लिए बेहतर प्रस्तावों के साथ और PSGI कंपनियों में ठोस प्रस्तावों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए दबाव बनाया जाय।
* सभी स्तरों पर **संगठन** को मजबूत करने के लिए काम करना होगा और अखिल भारतीय स्टार से लेकर शाखा स्तर तक ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित किया जाय । अगस्त के दूसरे पखवाड़े के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर ट्रेड यूनियन कक्षा को आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

हमें विश्वास है कि पूरे भारत में हमारी इकाइयाँ सचिवालय के निर्णयों को सही भावना से लागू करने के लिए उचित संगठनात्मक कदम उठाएंगी।

अभिवादन सहित



कॉमरेड श्रीकांत मिश्र

महासचिव (ए.आई.ई.ए.)